vinetur

रूसी आयात प्रतिबंधों को EEU न्यायालय में चुनौती देने पर विचार कर रहा है आर्मेनिया

अर्थव्यवस्था मंत्री गेवरग पापोयान ने कहा कि यूरेशियन आर्थिक आयोग द्वारा ब्रांडी, वाइन, कृषि उपज और डेयरी निर्यात पर पाबंदियां नहीं हटाने पर येरेवान अपील करेगा

गुरुवार, 19 नवंबर 2026



अर्थव्यवस्था मंत्री गेवरग पापोयान ने बुधवार, 18 नवंबर को कहा कि यदि इस गुट की कार्यकारी संस्था येरेवान का समर्थन नहीं करती है, तो आर्मेनिया रूस के साथ अपने व्यापार विवाद को यूरेशियन आर्थिक संघ के न्यायालय में ले जाने का विकल्प खुला रखे हुए है। सरकार रूसी प्रतिबंधों को पलटने की कोशिश कर रही है, जिनसे आर्मेनिया के निर्यात की एक व्यापक श्रेणी प्रभावित हुई है।

संसद में पत्रकारों से बात करते हुए पापोयान ने कहा कि यदि संघ की नियामक संस्था यूरेशियन आर्थिक आयोग आर्मेनिया के पक्ष में फैसला नहीं करती है, तो देश EEU न्यायालय में अपील कर सकता है। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि येरेवान तब तक औपचारिक बहस के लिए दबाव नहीं डालना चाहता, जब तक उसे अपने पक्ष में समर्थन मिलने का भरोसा न हो।

पापोयान ने कहा कि सरकार जल्द सकारात्मक नतीजा हासिल करने के लिए काम कर रही है। उनकी टिप्पणी से संकेत मिला कि आर्मेनिया विवाद को न्यायिक निकाय तक ले जाने से पहले गुट की आंतरिक प्रक्रियाओं के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

विवाद की जड़ रूसी आयात प्रतिबंध हैं, जो अप्रैल के अंत में शुरू हुए और आर्मेनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्यात श्रेणियों तक फैल गए। आर्मेनियाई अधिकारियों और मॉस्को के पूर्व सार्वजनिक बयानों के मुताबिक, रूसी नियामकों ने आर्मेनियाई वस्तुओं को निशाना बनाते हुए स्वच्छता और लेबलिंग संबंधी उल्लंघनों का हवाला दिया है। इन उपायों से मिनरल वॉटर, ब्रांडी, वाइन, कटे हुए फूल, फल, सब्जियां, मछली, डेयरी उत्पाद और अन्य वस्तुएं प्रभावित हुई हैं।

आर्मेनिया के पेय उत्पादकों के लिए यह दबाव खास तौर पर अहम है, क्योंकि रूस लंबे समय से आर्मेनियाई ब्रांडी, वाइन और बोतलबंद पेय का एक बड़ा बाजार रहा है। लंबे समय तक व्यवधान से बिक्री को नुकसान पहुंच सकता है और ऐसे समय में किसी एक बड़े निर्यात गंतव्य पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम उजागर हो सकता है, जब राजनीतिक तनाव व्यापार को प्रभावित कर रहा है।

यूरेशियन आर्थिक आयोग को मूल रूप से 3 नवंबर को आर्मेनिया की शिकायत पर चर्चा करनी थी। आर्मेनिया के अनुरोध पर उस बैठक को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया। 10 नवंबर के लिए तय एक और बैठक भी नहीं हुई और आर्मेनिया के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने इस देरी की सार्वजनिक रूप से कोई वजह नहीं बताई।

पापोयान की टिप्पणी आर्मेनिया और रूस के बीच व्यापक राजनीतिक तनाव के बीच आई। इसकी एक वजह यूरोपीय संघ के साथ येरेवान के बढ़ते संबंध हैं। मार्च 2025 में आर्मेनिया की संसद ने देश की EU में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने वाला कानून पारित किया। इससे यह सवाल और तीखा हो गया कि मॉस्को के नेतृत्व वाले EEU की सदस्यता के साथ आर्मेनिया अपनी यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं में संतुलन कैसे बनाएगा।

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूसी अधिकारी बार-बार कह चुके हैं कि EU की सदस्यता EEU में बने रहने के साथ संगत नहीं है। बेलारूस, कजाखस्तान और किर्गिस्तान भी इस संघ के सदस्य हैं। मॉस्को ने आर्मेनिया से जनमत-संग्रह के जरिए मतदाताओं को दोनों गुटों में से किसी एक को चुनने देने का आग्रह किया है।

पापोयान ने इस विचार को खारिज किया कि आर्मेनिया एक बाजार की जगह दूसरे बाजार को अपनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था मंत्री के तौर पर उनका लक्ष्य आर्मेनिया के निर्यात को EU और EEU, दोनों में बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 में EU को आर्मेनियाई निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, जबकि EEU को कुछ वस्तुओं की खेप घट गई है।

यूरोपीय संघ ने हाल में आर्मेनिया के अधिकांश निर्यात, कृषि उत्पादों समेत, को अस्थायी रूप से शुल्क-मुक्त पहुंच दी है। इस कदम से रूसी प्रतिबंधों के कारण हुए कुछ नुकसान की भरपाई में मदद मिल सकती है। फिर भी, जिन क्षेत्रों ने उस बाजार के इर्द-गिर्द अपने ब्रांड, लॉजिस्टिक्स और वितरण माध्यम विकसित किए हैं, उनके लिए अल्पावधि में रूसी मांग की जगह दूसरा बाजार खोजना मुश्किल होगा। इनमें खास तौर पर मादक पेय और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं।

पापोयान ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि आर्मेनिया 2027 में कई दिशाओं में निर्यात बढ़ाएगा और रूस के नेतृत्व वाले गुट के साथ पहले के व्यापार स्तर पर लौटेगा। उनकी टिप्पणी से संकेत मिला कि येरेवान अब भी उम्मीद कर रहा है कि EEU के भीतर व्यापक टूट के बिना इस विवाद को संभाला जा सकता है।

मंत्री ने 18 और 19 नवंबर के लिए तय मॉस्को की रद्द हुई कार्य-यात्रा से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। मंगलवार, 17 नवंबर को प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के कार्यालय ने सरकार के पोर्टल e-gov.am पर एक औपचारिक निर्णय प्रकाशित किया था, जिसमें पापोयान को व्यापार नीति और औद्योगिक प्राथमिकताओं पर EEU परामर्श के लिए रूसी राजधानी भेजा जाना था। आदेश में कहा गया था कि येरेवान लौटने के तीन दिनों के भीतर उन्हें रिपोर्ट सौंपनी होगी।

पापोयान ने कहा कि वे आर्मेनिया में ही रहे, क्योंकि उनके दो समकक्षों के आखिरी समय में हट जाने के बाद प्रस्तावित मंत्रिस्तरीय परामर्श का मकसद खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि EEU के अर्थव्यवस्था मंत्रियों को सीमा-शुल्क दरों और व्यापार नियमों पर चर्चा करनी थी, लेकिन इसके बाद आर्मेनिया ने मंत्रिस्तरीय स्तर पर भाग न लेने का फैसला किया। उनके मुताबिक, बैठक में एक उपमंत्री ने हिस्सा लिया।

यह व्यापार विवाद ऊर्जा को लेकर रूस की चेतावनियों के बीच भी जारी रहा है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि यदि आर्मेनिया EU के साथ एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो वह ऊर्जा से जुड़ी रियायती व्यवस्थाएं गंवा सकता है और उसे फिलहाल मिल रही रियायती दर के बजाय रूसी प्राकृतिक गैस बाजार भाव पर खरीदनी पड़ सकती है। इससे सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक गठजोड़ को लेकर मतभेदों से पहले ही तनावपूर्ण संबंधों पर दबाव की एक और परत जुड़ गई है।

फिलहाल, आर्मेनिया सभी उपलब्ध विकल्प खुले रखते हुए संस्थागत स्तर पर सीधे टकराव से बचने की कोशिश करता दिख रहा है। पापोयान की टिप्पणी से जाहिर हुआ कि येरेवान अब भी EEU के भीतर बातचीत या प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए समाधान तलाश रहा है, लेकिन आर्मेनियाई वस्तुओं पर रूसी प्रतिबंध जारी रहने पर मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार है।